साप्ताहिक
Live not just breaTHE

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/22-23

दि कार्मिक पोस्ट

Global School Of Excellence, Obedullaganj

वर्ष : 9, अंक : 33 (प्रति बुधवार),इन्दौर, 3 अप्रैल 2024 से 9 अप्रैल 2024 पेज :8 कीमत : 3 रुपये

भोजन बर्बादी है एक वैश्विक त्रासदी, 78 करोड़ लोगों को नहीं मिलता भरपेट भोजन

युगांडा में भोजन की बर्बादी का एक दृश्य. दुनिया भर में हर साल इतना भोजन बर्बाद होता है जिससे करोड़ों लोगों को भेरपेट भोजन मिल सकता है. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (ह्श्वक्र) की एक नई रिपोर्ट दर्शाती है कि एक तरफ़, एक-तिहाई मानव आबादी, खाद्य असुरक्षा से जूझ रही है, वहीं हर दिन, एक अरब आहार खुराकों के समतुल्य खाद्य सामग्री बर्बाद हो जाती है. यूएन पर्यावरण कार्यक्रम की कार्यकारी निदेशक इंगेर ऐंडरसन ने कहा कि खाद्य बर्बादी एक वैश्विक त्रासदी है. दुनिया भर में भोजन ऐसे समय में बर्बाद हो रहा है जब लाखों-करोड़ों लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है. उन्होंने बताया कि इस वजह से ना केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, बल्कि जलवायु परिवर्तन, जैवविविधता हानि और प्रदूषण की चुनौतियाँ भी गहरी हो जाती हैं.

यूएन एजेंसी की ÒFood Waste Index Report 2024' रिपोर्ट बताती है कि 2022 में लगभग एक अरब टन भोजन बर्बाद हो गया. क़रीब 20 फ़ीसदी भोजन कूड़े में फेंक दिया जाता है. उपभोक्ताओं के लिए कुल उपलब्ध भोजन में से लगभग 19 फ़ीसदी खाद्य सामग्री की हानि, फुटकर दुकानों, खाद्य सेवाओं और घर-परिवारों में हुई है. यह भोजन बर्बादी, सप्लाई चेन यानि खेत में उपज से लेकर दुकान में बिक्री तक - में होने वाली भोजन हानि से अलग है, जोकि यूएन खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार क़रीब 13 प्रतिशत है. रिपोर्ट दर्शाती है कि खाद्य सामग्री की अधिकाँश बर्बादी घर-परिवारों में होती है, जिसे क़रीब 63.1 करोड़ टन आँका गया है. यह कुल भोजन बर्बादी का 60 प्रतिशत हिस्सा है. भोजन बर्बादी की मात्रा, खाद्य सेवा क्षेत्र में 29 करोड़ टन और फुटकर सैक्टर में 13.1 करोड़ टन है. औसतन, हर व्यक्ति एक वर्ष में 79 किलोग्राम भोजन की बर्बादी के लिए ज़िम्मेदार है. यह विश्व में भूख से प्रभावित हर व्यक्ति के लिए हर दिन 1.3 आहार खुराकों के समतुल्य है.

केवल धनी देशों की समस्या नहीं- भोजन बर्बादी की चुनौती महज़ सम्पन्न देशों तक सीमित नहीं है, और इस विषय में धनी व निर्धन देशों के बीच की दूरी कम हो रही है.

उच्च-आय, ऊपरी-मध्य आय, और निम्नतर-मध्य आय वाले देशों में घर-परिवारों में होने वाली औसत खाद्य बर्बादी

में, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष सात किलोग्राम का अन्तर है. मगर, शहरी और ग्रामीण आबादियों में यह तस्वीर अलग है. मध्य-आय वाले देशों में ग्रामीण इलाक़ों में भोजन की बर्बादी कम होती है. इसकी एक वजह, बची-खुची हुई खाद्य सामग्री को फिर से इस्तेमाल में लाया जाना हो सकती है, जैसेकि पालतु पशुओं के खाने और खाद या चारे के लिए.रिपोर्ट में सिफ़ारिश की गई है कि खाद्य बर्बादी में कमी लाने के प्रयासों को मज़बूत करना होगा और शहरों में भी सड़े हुए भोजन को खाद के रूप में इस्तेमाल करना होगा.

खाद्य बर्बादी व जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट बताती है कि खाद्य बर्बादी के स्तर और औसत तापमान में सीधा सम्बन्ध है. गर्म जलवायु वाले देशों में घर-परिवारों में प्रति व्यक्ति ज़्यादा मात्रा में भोजन बर्बाद होती है, चूँकि वहाँ ताज़ा भोजन खाने की प्रवृत्ति है और खाद्य संरक्षण के लिए शीतलन उपकरण (रेफ़्रिजरेटर) का अभाव हो सकता है.

ऊँचे तापमान, ताप लहरों या सूखे के कारण भोजन का सुरक्षित ढंग से भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण चुनौतीपूर्ण हो जाता है, जिससे बड़ी मात्रा में भोजन की बर्बादी या हानि होती है. भोजन हानि और बर्बादी, 10 प्रतिशत वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिए ज़िम्मेदार है, जोकि विमानन सैक्टर में कुल उत्सर्जन का पाँच गुना है. इसके मद्देनज़र, यूएन विशेषज्ञों ने भोजन बर्बादी से होने वाले उत्सर्जन में कटौती लाने पर बल दिया है.

निर्वाचन कार्यालय में देना होगी चुनाव से संबंधित मुद्रित सामग्री की प्रति

इंदौर लोकसभा चुनाव के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के व्यय पर कड़ी नजर रखने के लिए समस्त केबल आपरेटर एवं प्रिटिंग प्रेस मालिकों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों से अवगत कराया गया है।

निर्देशों में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान केबल आपरेटर एवं प्रिटिंग प्रेस मालिकों को विशेष एहतियात बरतनी है। उनके किसी भी प्रसारण एवं मुद्रण से शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका होगी तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रिटिंग प्रेस मालिकों से कहा गया है कि उनके द्वारा चुनाव संबंधी जो सामग्री प्रकाशित की जाती है, उसकी चार प्रतियां मय घोषणा पत्र, जिला निर्वाचन कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध कराई जाए। प्रकाशित की गई सामग्री में प्रिटिंग लाइन अवश्य दी जाए, जिसमें मुद्रक, प्रकाशक का नाम, पता और प्रकाशित सामग्री की संख्या दर्ज हो। इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले प्रिटिंग प्रेस मालिकों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने केबल आपरेटरों को पेड न्यूज के संबंध में सजग और सतर्क रहने को कहा है। कोई ऐसी न्यूज जो राजनैतिक दल विशेष को लाभ पहुंचाए जाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रानिक मीडिया में दिखाई जाती है, वह पेड न्यूज की श्रेणी में आएगी। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला एवं राज्य स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति का गठन किया गया है। यह समिति 24 घंटे इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रसारण पर नजर रखने के लिए गठित की गई है। केबल आपरेटरों से कहा गया है कि वे आयोग के निर्देशों का आवश्यक रूप से पालन करें। केबल आपरेटर द्वारा जिस सामग्री का प्रसारण किया जाता है उसके प्रसारण पूर्व प्रसारणकर्ता से घोषणा पत्र भी प्राप्त करें। वेबसाइट एवं सोशल मीडिया के अन्य प्रकारों पर भी नजर रखने की व्यवस्था की गई है। राजनैतिक दलों द्वारा बल्क में किए जाने वाले एमएमएस एवं वॉयस मैसेज पर भी नजर रखी जायेगी । जिन उम्मीदवारों द्वारा नामनिर्देशन पत्र दाखिल किए जायेगें उनसे शपथ पत्र में ईमेल आईडी एवं सोशल मीडिया एकाउंट की जानकारी ली जायेगी।

आपबीती-जापानी क़स्बे ने निकाला, कम अपशिष्ट समाज का रास्ता

कसूमी फ़ूजीता, जापान के दक्षिण-पश्चिमी इलाक़े ओसाकी में जब एक कूड़ाघर पूरी तरह भर गया तो उस कूड़े को भस्म करके राख बनाने के लिए एक विशाल भट्टी बनाने का विकल्प ही तार्किक नज़र आया. मगर इसके बदले, उस क़स्बे ने रीसायकलिंग के बार में गम्भीर रुख़ अपनाने का निर्णय लिया. 30 मार्च को मनाए जाने वाले अन्तरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस के अवसर पर, ओसाकी की पार्षद कसूमी फ़ूजीता ने, यूएन न्यूज़ को बताया कि उन्हें किस बात से प्रेरणा मिली.

कसूमी फ़ूजीता, वर्ष 2021 में स्थानीय नगरपालिका, व्यवसाय सैक्टर और स्थानीय समुदाय के साथ काम करने के लिए पहुँची थीं और उनका उद्देश्य, ओसाकी क़स्बे को एक अधिक टिकाऊ भविष्य की की ख़ातिर तैयार करने में मदद करना था. आज लगभग 12 हज़ार की आबादी वाला ओसाकी क़स्बा, अपने यहाँ उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट यानि कूड़े का 80 प्रतिशत हिस्सा रीसायकल यानि पुनर्चक्रण करता है. इस तरह ये क़स्बा, कूड़े को जलाकर भस्म करने के लिए विशाल भट्टी बनाने से बच गया. कसूमी फ़ूजीता कहती हैं... मैं सदैव से ही जलवायु संकट से सम्बन्धित किसी क्षेत्र में काम करना चाहती थी, और बहुत मज़बूती से यह महसूस करती थी कि मुझे उस बारे में क़दम उठाना होगा. इसीलिए मैं ओसाकी में पहुँची. चूँकि कोई अपशिष्ट भट्टी नहीं है, इसलिए केवल नीले बोरों को ही भस्म किए बिना, सीधे कूड़ा घर में भेजा जाता है. अन्य 26 श्रेणियों वाले बोरों को छाँटकर, उचित तरीक़े से उन्हें रीसायकल किया जाता है. उदाहरण के लिए, प्लास्टिक को विभिन्न श्रेणियों में छाँटा जाता है और उसके बाद उसे दबाकर बाँध दिया जाता है. फिर दबे हुए प्लास्टिक कूड़े को, देश भर में रीसायकलिंग फ़ैक्टरियों में भेज दिया जाता है.

हम सभी कुछ ना कुछ ठोस कर सकते हैं- खाद्य अपशिष्ट सप्ताह में तीन बार, नीली बाल्टी में एकत्र किया जाता है. फिर उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में कूट दिया जाता है. कटे-टूटे पौधों को भी यहाँ लाया जाता है, और उन्हें खाद्य अपशिष्ट में मिला दिया जाता है. कटे-टूटे पौधों में बहुत से देसी सूक्ष्म तत्व यानि microorganisms होते हैं. जब सड़ या गल जाते हैं तो वो अपशिष्ट एक अच्छी खाद का रूप ले लेता है और उसका लगभग पूरा हिस्सा ही, ओसाकी के खेतों में प्रयोग होता है. मेरे विचार में प्रक्रिया बहुत सरल है और इसे दुनिया भर में कहीं भी प्रयोग किया जा सकता है. दरअसल, हमारी प्रक्रिया को इंडोनेशिया में शुरू किया गया है. ओसाकी के टाउन अधिकार और रीसायकलिंग केन्द्र के कर्मचारी, खाद्य अपशिष्ट को छाँटने और उसकी खाद बनाने की तकनीक दिखाने के लिए, इंडोनेशिया गए. यह प्रक्रिया एक ऐसी समस्या का समाधान बन सकती है जिसका सामना, बहुत से विकासशील देश, इस समय कर रहे हैं. मैं बड़ी शिद्दत से यह मानती हूँ कि लोगों को उस प्रक्रिया के बारे में ज़रूर अधिक जानकारी हासिल करनी चाहिए कि हमारे इस्तेमाल के बाद, चीज़ों का हाल क्या होता है, और अपशिष्ट प्रबन्धन या रीसायकलिंग का मुद्दा कितना जटिल है. ऐसा करके लोग, यह समझ सकेंगे कि अपशिष्ट या कूड़े को दरअसल कम किया जा सकता है. कारोबारों और स्थानीय सरकारों को भी इस स्थिति को समझना होगा. हमें ठोस परिणाम हासिल करने के लिए, हर किसी को सक्रिय और प्रेरित करना होगा.

ईवी का बढ़ा क्रेज- युवाओं की भी बनी पसंद

भोपाल/ मप्र में अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदने का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि जिस रफ्तार से पेट्रोल-डीजल वाहनों की बिक्री होती है, उसी रफ्तार से अब ईवी वाहनों की बिक्री भी होने लगी है। इसकी वजह है युवाओं में इसको लेकर बढ़ता क्रेज। इसका अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि ऑफ सीजन में भी अकेले भोपाल में आधा दर्जन से अधिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन रजिस्टर्ड हो रहे हैं। यह संख्या पेट्रोल-डीजल की संख्या से आधी है। इनमें दो पहिया इलेक्ट्रिक व्हीकल सहित तीन पहिया बैटरी कमर्शियल वाहन एवं बैटरी से संचालित होने वाले चार पहिया निजी श्रेणी के वाहन शामिल है। कई इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता कंपनियों ने हाल ही में दामों में कटौती करने की घोषणा की है। इसकी वजह से इसकी बिक्री के और जोर पकडने़ की संभावना है। इसी के साथ अब इन वाहनों में सुरक्षा फीचर पहले से ज्यादा अपडेट कर दिए गए हैं। कम समय में चार्ज होने के बाद दो पहिया वाहन 290 किलोमीटर तक का माइलेज उपलब्ध करवा रहे हैं। एक लाख से कम कीमत में आने वाले चुनिंदा वाहनों को खरीदने ग्राहकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है।

एक प्रतिशत है रजिस्ट्रेशन चार्ज मध्य प्रदेश के भोपाल सहित किसी भी जिले में इलेक्ट्रॉनिक दो पहिया, तीन पहिया एवं चार पहिया वाहन खरीदकर रजिस्टर्ड करने पर एक्स शोरूम प्राइस का एक प्रतिशत मूल्य रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में सरकार के खाते में जमा करना होता है। जबकि पेट्रोल-डीजल गाडियों़ के लिए यह 10 प्रतिशत है। मध्य प्रदेश सरकार की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी में नए प्रस्ताव भी शामिल किये जा रहे हैं। इससे आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल चलने वाले वाहन चालकों को फायदा पहुंचेगा।

पेट्रोल के झंझट से मिली राहत इस वक्त पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है। कई शहरों में पेट्रोल 110 रुपए प्रति लीटर से भी ऊपर पहुंच चुका है। ऐसे में इलेक्ट्रिक स्कूटर इन लोगों के बजट के लिए काफी बेहतर साबित हो रहे हैं। एक बार फुल चार्ज करने पर आप इनसे करीब 100 किलोमीटर तक का सफर कर सकते हैं। आपको रोज-रोज पेट्रोल डलवाने के झंझट से भी मुक्ति मिलती है।

ओण दिवस- क्या है जंगलों को आग से बचाने का शीतलाखेत मॉडल?

बैंगलुर। साल दर साल उत्तराखंड में बढ़ती वनाग्नि की घटनाओं और इससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए सरकारी स्तर पर हर वर्ष फायर सीजन शुरू होने से पहले वन विभाग और राज्य सरकार की ओर से कई तरह की योजनाओं का दावा किया जाता है, लेकिन वनाग्नि की घटनाओं और इससे होने वाले नुकसान के आंकड़ों को देखें तो इन योजनाओं और इन दावों का कोई खास फायदा होता नजर नहीं आता है। ऐसे में अल्मोड़ा जिले के शीतलाखेत में कुछ लोगों ने जंगलों में लगने वाली आग की घटनाओं को कम करने के लिए एक नया तरीका ईजाद किया है।

इसे शीतलाखेत मॉडल नाम दिया गया है। इस मॉडल से प्रेरित होकर अल्मोड़ा के जिला प्रशासन ने हर वर्ष एक अप्रैल को ओण दिवस मनाने की घोषणा की है और पिछले तीन सालों से अल्मोड़ा में ओण दिवस मनाया जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शीतलाखेत मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने की बात कही थी, हालांकि तमाम सरकारी घोषणाओं के तरह की उनकी यह घोषणा भी अब तक हवा-हवाई ही साबित हुई है। शीतलाखेत मॉडल ओण जलाने पर आधारित है। पर्वतीय इलाकों में खरीफ की फसलों के लिए खेत तैयार करते समय खेतों, बंजर भूमि, खेत की मेड़ में, दीवारों में उग आई झाड़ियों, खरपतवारों को काटकर, सुखाकर जलाया जाता है। इसे प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में ओण, आड़ा या केड़ा जलाना कहा जाता है। माना जाता है कि जंगलों में लगने वाली आग की 90 प्रतिशत घटनाएं ओण या आड़ा जलाने के कारण होती हैं। शीतलाखेत मॉडल दरअसल पर्वतीय ग्रामीण समाज में अतीत से चली आ रही ओण जलाने की परंपरा को समयबद्ध, व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने का मॉडल है। शीतलाखेत मॉडल को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले स्याही देवी विकास मंच, शीतलाखेत के संयोजक गजेन्द्र पाठक कहते हैं कि वह काफी समय से महसूस कर रहे थे कि कोसी, गगास, रामगंगा और सुयाल जैसी गैर हिमानी नदियों के कैचमेंट एरिया में साल दर साल जंगलों में आग लग रही है और इसी रफ्तार से इन नदियों के साथ ही इस क्षेत्र के प्राकृतिक जलस्रोतों, धारों और गाड-गदेरों का पानी भी कम होता जा रहा है। उन्होंने क्षेत्र में काम करने वाले जंगल के दोस्त, प्लस अप्रोच फाउंडेशन और ग्रामोद्योग विकास संस्थान जैसे संगठनों से संपर्क किया और इन नदियों के कैचमेंट क्षेत्र में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए प्रयास करने का प्रस्ताव रखा। गजेन्द्र पाठक के अनुसार आमतौर पर ओण उस दौरान जलाये जाते हैं, जब गर्मियों का मौसम शुरू हो जाता है। यह वह मौसम होता है, जब जंगलों में चीड़ के पत्ते यानी पिरुल गिरने लगता है और तेज हवाएं चलती हैं। तेज हवाओं के बीच ओण जलाते समय आग की कोई चिंगारी उड़कर आसपास के जंगल तक पहुंच जाती है और वहां सूखी पिरुल तुरंत आग पकड़ लेती है। ऐसे में ओण जलाने की परंपरा को व्यवस्थित करने की योजना बनाई गई। इसके लिए शीतलाखेत के आसपास के 40 गांवों के लोगों से संपर्क किया गया और उन्हें इस मुहिम से जोड़ा गया। इसमें करना सिर्फ इतना था कि खेतों की दीवारों, मुंडेरों और आसपास की बंजर जमीन में उगी झाड़ियों को सर्दियों के मौसम में ही काट देना था और 31 मार्च से पहले-पहले जला देना था। वह कहते हैं कि अप्रैल से एक तरफ जहां गर्मी अचानक बढ़ जाती है, वहीं दूसरी तरफ चीड़ की पत्तियां गिरने लगती हैं और तेज हवाएं चलने का दौर भी शुरू हो जाता है। 31 मार्च तक ओण जलाने का काम खत्म करने के बाद 1 अप्रैल को ओण दिवस मनाने की परंपरा शुरू की गई। यह परंपरा 2022 में शुरू की गई थी।

आठ की बजाय अब 12 दिन झेलने पड़ते हैं लू के थपेड़े

मुंबई। एक नए अध्ययन में पाया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में लू या हीटवेव की घटनाएं धीमी हो रही हैं और वे बड़े इलाकों में भारी तापमान के साथ अधिक लोगों को लंबे समय तक झुलसा रही हैं। साइंस एडवांसेज में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, 1979 के बाद से, दुनिया भर में लू 20 फीसदी अधिक धीमी गति से चल रही हैं, जिसका अर्थ है कि अधिक लोग लंबे समय तक लू की चपेट में आ रहे हैं, ऐसा 67 फीसदी अधिक बार हो रहा है। अध्ययन में पाया गया कि लू के दौरान भारी तापमान 40 साल पहले की तुलना में अधिक है और गर्मी का क्षेत्र भी बढ़ गया है।

अध्ययन के मुताबिक, लू पहले भी खतरनाक हो चुकी हैं, लेकिन यह अधिक व्यापक है और न केवल तापमान और क्षेत्र पर गौर करती है, बल्कि भारी गर्मी कितने समय तक रहती है और यह महाद्वीपों में कैसे फैलती है, इस पर भी गौर किया गया है। अध्ययन में कहा गया है कि 1979 से 1983 तक, दुनिया भर में लू के थपेड़े औसतन आठ दिनों तक चलते थे, लेकिन 2016 से 2020 तक यह 12 दिनों तक बढ़ गए। अध्ययन में कहा गया है कि लंबे समय तक चलने वाली लू के थपेड़ों से यूरेशिया विशेष रूप से अधिक प्रभावित हुआ। अध्ययन के अनुसार, अफ्रीका में लू सबसे अधिक धीमी हुई, जबकि उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में समग्र परिमाण में सबसे बड़ी वृद्धि देखी गई, जो तापमान और क्षेत्र को मापता है। अध्ययन में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि जलवायु परिवर्तन लू को कई मायनों में और भी खतरनाक बना देता है। ठीक उसी तरह जैसे ओवन में, जितनी अधिक देर तक गर्मी रहती है, उतनी ही अधिक चीजें पकती हैं, लू के मामले में यहां लोग हैं। लू धीमी और इतनी धीमी गति से चल रही हैं कि मूल रूप से इसका मतलब है कि वहां लू है और वे लू इस क्षेत्र में लंबे समय तक रह सकती हैं। लू का हमारे मानव समाज पर प्रतिकूल प्रभाव बहुत बड़ा होगा और यह साल-दर-साल बढ़ेगा। अध्ययन में बताया गया है कि शोधकर्ताओं ने कंप्यूटर सिमुलेशन आयोजित किया, जिसमें दिखाया गया कि यह परिवर्तन कोयले, तेल और प्राकृतिक गैस के जलने से होने वाली गर्मी को फंसाने वाले उत्सर्जन के कारण थी। अध्ययन में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के बिना एक दुनिया का अनुकरण करके जलवायु परिवर्तन के निशान पाए गए और यह निष्कर्ष निकाला गया कि यह पिछले 45 वर्षों में देखी गई भीषण लू का उत्पादन नहीं कर सकता है। अध्ययन मौसम के पैटर्न में होने वाले बदलावों पर भी गौर करता है जो लू को फैलाते हैं। वायुमंडलीय तरंगें जो मौसम प्रणालियों को अपने साथ ले जाती हैं, जैसे कि जेट स्ट्रीम, कमजोर हो रही हैं, इसलिए वे लू को तेजी से नहीं ले जा रही हैं, अधिकांश महाद्वीपों में पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं, बल्कि सभी महाद्वीपों में ऐसा देखा जा रहा है।

7000 से अधिक जलाशयों की अंतरिक्ष से निरंतर की जा रही है निगरानी

नई दिल्ली अधिकांश उपग्रहों को कई कार्यों को पूरा करने के लिए पांच से 10 साल के मिशन के लिए कक्षा में स्थापित किया जाता है। मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्टर रेडियोमीटर (एमओडीआईएस) ले जाने वाले उपग्रहों के कई कार्यों में से एक दुनिया भर के जलाशयों की निगरानी करना है। दुनिया के मीठे या ताजे पानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इन जलाशयों में है।

दुनिया भर में पानी की निगरानी के लिए रिमोट सेंसिंग महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी देश नियमित रूप से अपने जल स्तर को रिकॉर्ड नहीं करते हैं या यदि वे ऐसा करते हैं तो उन आंकड़ों को साझा करने का विकल्प नहीं चुनते हैं। पानी की निगरानी के सटीक आंकड़े न केवल जल संसाधन प्रबंधन बल्कि नीतिगत निर्णय लेने में भी सहायता करते हैं। एमओडीआईएस ले जाने वाले उपग्रह पिछले 24 वर्षों से यह कार्य कर रहे हैं। 2011 में लॉन्च किए गए विजिबल इन्फ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर सुइट वाले उपग्रह प्रौद्योगिकी का एक नया संस्करण ले जाते हैं। हर एक सेंसर पर थोड़ी अलग तकनीकों के साथ, एमओडीआईएस से विजिबल इन्फ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर सुइट तक आंकड़े निरंतरता न केवल नए आंकड़े को सत्यापित करने के लिए बल्कि ऐतिहासिक आंकड़ों को संरक्षित करने के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। नासा के साथ सहयोग किया गया यह शोध नेचर सब-जर्नल, साइंटिफिक डेटा में प्रकाशित हुआ है। शोध में शोधकर्ता ने कहा, हम इस अवधि का उपयोग यह पहचानने के लिए करना चाहते हैं कि क्या हम एमओडीआईएस के बंद होने के बाद विजुअल इन्फ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर सुइट का उपयोग कर सकते हैं। 2000 से 2012 तक, शोधकर्ताओं ने एमओडीआईएस के अवलोकनों का उपयोग किया और 2012 से 2021 तक, विजिबल इन्फ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर सुइट अवलोकनों का उपयोग किया गया। फिर दोनों सेंसर से हासिल किए गए आंकड़ों को मिलाकर उनकी तुलना 2000-2021 के एमओडीआईएस अवलोकनों से की, यह देखने के लिए कि क्या रुझान स्थिर हैं या नहीं। पहले, उपग्रह झीलों और जलाशयों को केवल उनके आकार और पानी की मात्रा से मापते थे। यह अध्ययन वाष्पीकरण के माध्यम से पानी के नुकसान को भी मापता है, जो जल संसाधनों से जुड़ी गतिशीलता की अधिक संपूर्ण तस्वीर पेश करता है। शोध में कहा गया है कि शोधकर्ताओं की टीम ने जलाशयों का अध्ययन करने के लिए कई साल बिताए हैं, अपने पिछले अध्ययनों को आगे बढ़ाने के लिए अधिक जलाशयों और अधिक बदलावों को जोड़कर अपने शोध के दायरे को बढ़ाया है। दुनिया भर में 164 बड़े जलाशयों तक खुली पहुंच, परिचालन डेटासेट विवरण क्षेत्र, ऊंचाई, भंडारण, वाष्पीकरण दर और वाष्पीकरण मात्रा की जानकारी देता है, जिसमें 151 मानव निर्मित जलाशय और 13 नियमित प्राकृतिक झीलें शामिल हैं। यह शोध पर्यावरण अनुसंधान और जल प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण आंकड़े प्रदान करता है। शोध के मुताबिक, ये उत्पाद विकास मूल रूप से 10 साल पहले अध्ययनों पर आधारित थे। शोधकर्ता ने शोध में उदाहरण देकर कहा कि, 10 साल पहले, 34 जलाशय थे, लेकिन हमने इस उत्पाद में संख्या, परिवर्तन और सटीकता बढ़ाना जारी रखा। शोध में कहा गया कि वैश्विक स्तर पर लगभग 7000 से अधिक जलाशय हैं, जिनमें छोटे से लेकर बड़े जलाशय शामिल हैं। शोधकर्ताओं ने 151 मानव निर्मित जलाशयों से वैश्विक क्षमता का लगभग 45 से 46 प्रतिशत हासिल करने के लिए आंकड़े एकत्र किए हैं। शोधकर्ताओं ने शोध के हवाले से कहा कि उनके अगले कदमों में इन आंकड़ों का उपयोग करके सूखा निगरानी प्रणाली विकसित करना और यह अध्ययन करना शामिल है कि मानव गतिविधियां जलाशयों में सूखे को कैसे प्रभावित करती हैं।

प्रत्याशियों को पर्यावरण का भी रखना होगा ख्याल

बस्ती। इस बार चुनाव में प्रत्याशी एवं राजनैतिक दलों को पर्यावरण का भी ख्याल रखना होगा। डीएम अंद्रा वामसी ने राजनैतिक दलों के साथ-साथ अधिकारियों को पर्यावरण के अनुकूल चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देश पर उन्होंने प्रचार सामग्रियों के उपयोग के कारण होने वाले पर्यावरणीय खतरों के मुद्दे पर सभी को सजग रहने की नसीहत दी है। कहा कि सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों को दिशानिर्देश प्रसारित किया गया है। पर्यावरण अनुकूल चुनाव दुनिया भर के विभिन्न देशों में लोकतंत्र का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। राजनैतिक दलों के साथ-साथ चुनाव पदाधिकारियों द्वारा चुनाव सामग्री में प्लास्टिक का उपयोग करना प्रतिबंधित है। सामग्री की छपाई और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे कार्य और पुस्तकों की भौतिक छपाई को कम करने और समय-समय पर ईसीआई द्वारा जारी सामग्री अनुदेशों की छपाई में पर्यावरण अनुकूल उपायों की बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008